समाचार पत्रिका

जुलाई 2026

जस्टिस इन माइनिंग नेट्वर्क

संदेश

प्रिय साथियों,

जोहार!

जैसा कि हम इस महीने के समाचार पत्रिका को संकलित करते हैं, हम आपको यहां संबोधित चुनौतियों के केंद्र में एक प्रश्न पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं: हम किस प्रकार का विकास चाहते हैं और किस कीमत पर?

पूरे भारत में, विकास की अवधारणा अभी भी खनन, उद्योगों, बांधों, राजमार्गों, स्मार्ट शहरों, डेटा केंद्रों और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का पर्याय है। लेकिन इस मुद्दे की कहानियाँ इस विकास का एक और पक्ष दिखाती हैं, एक विस्थापन, पारिस्थितिक तबाही, आजीविका का नुकसान और आदिवासी और स्थानीय आबादी के बढ़ते प्रतिरोध का। लोग बस्तर से राजस्थान, ओडिशा से मध्य प्रदेश तक जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। अरावली में खनन के खिलाफ प्रतिरोध, राउरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार के खिलाफ विरोध, केन-बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना का विरोध और खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के आसपास के संघर्षों से पता चलता है कि भूमि केवल एक वस्तु नहीं है। वन, नदियाँ, पहाड़ियाँ और पवित्र स्थान आदिवासी समूहों के लिए संस्कृति, पहचान, आजीविका और सामूहिक अस्तित्व के अभिन्न अंग हैं।

इस बीच, नए प्रकार के विकास से पारिस्थितिकीय चुनौतियां बढ़ रही हैं। आर्द्रभूमियों का जलाशयों में प्रस्तावित रूपांतरण, डेटा केंद्रों और एआई बुनियादी ढांचे का विकास और पानी और ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता हमें याद दिलाती है कि तकनीकी प्रगति पारिस्थितिक लागत पर भी आती है। युवा लोगों की जलवायु संबंधी चिंता आगे बताती है कि पर्यावरणीय क्षति केवल एक भौतिक आपदा नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक और सामाजिक भी है। पश्चिमी घाट, प्लास्टिक प्रदूषण और सीमा पार नदियों पर बहस भी एक अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि पारिस्थितिक प्रणालियों को राजनीतिक या आर्थिक सीमाओं के भीतर बाड़ नहीं लगाई जा सकती है। ये सभी बातें हमें राजनीतिक पार्टियों, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों, कॉर्पोरेट प्रमुखों और तथाकथित "प्रोफ़ेशनल्स" व "पॉलिसी मेकर्स" से यह सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारे अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों की भलाई की कीमत पर आर्थिक विकास को बनाए रखना इतना ज़रूरी है।

इसलिए इस समाचार पत्रिका में चर्चा किए गए संघर्षों की मांग है कि हम इस संकीर्ण प्रश्न से परे जाएं कि "कितना विकास?" अधिक बुनियादी प्रश्नों के बारे में सोचने के लिएः विकास किसके लिए? निर्णय कौन करता है? क़ीमत कौन चुकाता है? और किसके ज्ञान और अधिकारों को स्वीकार किया जाता है? हमें उम्मीद है कि यह मुद्दा हमें हाशिए से आवाज उठाने और न्याय, गरिमा, पारिस्थितिक स्थिरता और सामुदायिक स्वशासन के मूल्यों के माध्यम से विकास की फिर से कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

साथीगण

बुधन सिंह सिंकु

डॉ॰ पी॰एम॰ टोनी

क्या डिजिटलीकरण दलित और आदिवासी किसानों की जमीन हड़पने में मदद कर रहा है?

यह वीडियो भारत में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के प्रभावों का विश्लेषण करता है, जिसे पारदर्शिता और शासन को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, हालांकि विरोधाभासी रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेष रूप से आदिवासी और दलित किसानों को ज़ब्त करने का कारण बन सकता है। यह चर्चा झारखंड और आंध्र प्रदेश से संबंधित है, जहां भूमि प्रशासन के अलग-अलग ऐतिहासिक ढांचे का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इस विधि ने विसंगतियों का कारण बना है, स्वामित्व रिकॉर्ड को बदल दिया है, प्रलेखित भूमि जोत में कमी आई है, और किरायेदार किसानों को कल्याणकारी पहलों से बाहर कर दिया है। झारखंड में, पारंपरिक और सामुदायिक भूमि प्रथाएं-जैसे कब्रिस्तान, पवित्र क्षेत्र और सामूहिक संसाधन-डिजिटल प्रलेखन में खराब रूप से परिलक्षित होते हैं। अपर्याप्त सत्यापन और संचार स्थानीय अभिजात वर्ग और नौकरशाहों को दस्तावेजों में हेरफेर करने की अनुमति देता है। डिजिटल प्रणाली इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल फोन या डिजिटल साक्षरता तक सीमित पहुंच वाले समूहों को और हाशिए पर डाल देती है। इस चर्चा में कहा गया है कि डिजिटलीकरण केवल एक तकनीकी प्रयास नहीं है, बल्कि इसमें भूमि प्रबंधन और बिजली संरचनाओं की वर्तमान प्रणालियों को फिर से आकार देने की क्षमता है। यह समुदाय की भागीदारी, व्यवस्थित लेखा परीक्षा, प्रौद्योगिकी में जवाबदेही और अधिक मजबूत संस्थागत उपायों का सुझाव देता है जो धोखाधड़ी वाले विस्थापन को रोकते हैं।

इसे देखने के लिए यहां क्लिक करेंः https://www.youtube.com/watch?v=gxmBp0tL1uM

हम जानते हैं कि दूसरे मनुष्यों का शोक कैसे मनाना है- लेकिन पारिस्थितिक दुःख के बारे में क्या?

द गार्जियन की कहानी "पारिस्थितिक दुःख" पर प्रकाश डालती है, वह भावनात्मक पीड़ा जो व्यक्ति प्रकृति के विनाश, प्रजातियों के विलुप्त होने और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को देखते हुए महसूस करते हैं। यह तर्क देता है कि पर्यावरणीय क्षति न केवल एक वैज्ञानिक या पारिस्थितिक मुद्दा है, बल्कि एक गहरा भावनात्मक और सांस्कृतिक मुद्दा भी है। यहाँ इस बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए लुप्तप्राय प्रजातियों के विलुप्त होने, पक्षियों के निवास स्थान में कमी, मक्खियों के गायब होने, प्रवाल विरंजन और ग्लेशियर पिघलने जैसे उदाहरणों का उपयोग किया गया है। मानव मृत्यु दर के विपरीत, पारिस्थितिकीय नुकसान में अक्सर लोगों के शोक मनाने के लिए सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त अनुष्ठानों, भाषा या सामूहिक स्थानों की कमी होती है। अखबार इसलिए इसे एक निजी या तर्कहीन भावना के रूप में खारिज करने के बजाय सार्वजनिक रूप से पारिस्थितिक शोक को स्वीकार करने की वकालत करता है। स्मारकों, कहानी कहने और सांप्रदायिक अनुष्ठानों से समुदायों को यह याद रखने में मदद मिल सकती है कि प्राकृतिक दुनिया से अपना संबंध बनाए रखते हुए क्या खो गया है। अंत में, यह इस बात को रेखांकित करता है कि पारिस्थितिक क्षति लिए शोक मनाना प्रकृति की देखभाल, सुरक्षा और मरम्मत की दिशा में एक आवश्यक कदम हो सकता है।

अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करेंः

https://www.theguardian.com/enEnvironment/2026/jul/10/ecological-grief

काजीरंगा लग्जरी होटल परियोजना के विरोध के बीच असम भूमि अधिकार कार्यकर्ता प्रणब डोले गिरफ्तार



यह असम में स्वदेशी और भूमि-अधिकार कार्यकर्ता प्रणब डोले की गिरफ्तारी पर रिपोर्ट करता है, क्योंकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास एक नियोजित लक्जरी होटल परियोजना का विरोध कर रहा था। डोले, जो ग्रेटर काजीरंगा लैंड एंड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी (Greater Kaziranga Land and Human Rights Protection Committee) के संयोजक हैं, पांच सितारा होटल के लिए असम पर्यटन विकास निगम को इंगले पत्थर में भूमि के कथित हस्तांतरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। आदिवासी और कृषि समुदायों का कहना है कि उन्होंने सदियों से भूमि पर खेती की है और उनके पास ऐतिहासिक भूमि दस्तावेज और राजस्व प्राप्तियां हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह परियोजना काजीरंगा के आसपास उनकी आजीविका, चराई के मैदानों और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। डोले को पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के कई प्रावधानों के तहत विरोध प्रदर्शनों के दौरान अतिक्रमण, बाधा और हिंसा का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी ने भूमि अधिकारों की वकालत के अपराधीकरण पर चिंता जताई और असम में विकास, विस्थापन, पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी अधिकारों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए।

अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करेंः https://nenow.in/north-east-news/assam/assam-pranab-doley-arrested-amid-opposition-to-kaziranga-luxury-hotel-project.html

'हमारी नदी के लिए, हमारी पहाड़ियों के लिए': कैसे एक आदिवासी समुदाय राजस्थान में एक खनन कंपनी से लड़ रहा है



दीपावास और उसके आस-पास के गांवों के निवासी ओजस्वी मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित स्टील प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं।

लेख में राजस्थान के दीपावास गांव में एक प्रस्तावित लौह अयस्क खनन परियोजना के खिलाफ मीना आदिवासी समुदाय के प्रतिरोध का वर्णन किया गया है जो उनके जंगलों, जल स्रोतों, कृषि भूमि और नाजुक अरावली पहाड़ियों को नष्ट कर देगा। प्रस्तावित खनन पट्टा लगभग 180 हेक्टेयर है, जिसमें 149 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र शामिल है। लोगों के लिए, संघर्ष केवल एक खनन व्यवसाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि नदी, पहाड़ियों, आजीविका और पारिस्थितिक प्रणालियों के संरक्षण के लिए है जो उनके समुदाय को बनाए रखते हैं। निवासियों का मानना है कि खनन पहाड़ी ढलानों को नुकसान पहुंचाएगा, भूजल पुनर्भरण को कम करेगा, धाराओं को दूषित करेगा और मौसमी नदी के साथ-साथ जैव विविधता और चराई संसाधनों के लिए खतरा पैदा करेगा। समुदाय के सदस्यों ने पाया कि उनकी भूमि कथित रूप से उनकी सहमति के बिना पट्टे पर दी गई थी और उन्होंने खुद को संगठित किया, कानूनी प्रक्रियाओं को सीखा और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पर्यावरण मंजूरी और खनन अनुमतियों को चुनौती दी। उनकी लामबंदी से पता चलता है कि कैसे एक आदिवासी समुदाय जल, जंगल, जमीन और अरावली पारिस्थितिकी तंत्र पर सामूहिक अधिकारों का दावा करने वाले संगठित पर्यावरण रक्षक बनने के लिए उभरा।

अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://article-14.com/post/-for-our-river-for-our-hills-how-an-adivasi-community-is-fighting-a-mineing-company-in-rajasthan-6a545b9e1eef5

राउरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार में बाधा, भूमि अधिग्रहण को लेकर आदिवासियों का विरोध



पुलिस प्लाटून तैनात। तस्वीर: (OTV)

ओडिशा में राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के प्रस्तावित विस्तार, विशेष रूप से शीतल नगर में भूमि अधिग्रहण के लिए आदिवासी समुदायों के बढ़ते प्रतिरोध पर चर्चा की गई है। सैकड़ों आदिवासी निवासियों ने विरोध करते हुए कहा कि उनके पास भूमि पर पारंपरिक अधिकार हैं और मांग करते हैं कि विस्तार का काम रोका जाए। वे चिंतित हैं कि यह परियोजना उनकी आजीविका को खतरे में डाल देगी और अतिरिक्त विस्थापन का कारण बनेगी। प्रदर्शन के कारण पड़ोस में तनाव व्याप्त हो गया और सरकार ने कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की पांच प्लाटून तैनात की। यह बहस औद्योगिक विकास और आदिवासी जनजातियों की भूमि, आजीविका और प्रथागत अधिकारों के बीच एक बड़े संघर्ष का संकेत है। आर. एस. पी. (RSP) विस्तार औद्योगिक क्षमता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, लेकिन स्थानीय दबाव से पता चलता है कि विकास परियोजनाओं को भूमि स्वामित्व, विस्थापन, मुआवजे और सामुदायिक अनुमति के मुद्दों से अलग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यह मुद्दा विकास-प्रेरित विस्थापन और औद्योगिक ओडिशा में आदिवासी भूमि अधिकारों की स्वीकृति के बारे में महत्वपूर्ण विचार पैदा करता है।

अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://odishatv.in/odisha/Rourkela-steel-plant-expension-faces-hurdle-as-tribals-protest-over-land-acquisition-12159889

रायगढ़ में अडानी पावर परियोजना की सार्वजनिक सुनवाई में विरोध प्रदर्शन; ग्रामीणों ने प्रदूषण और रोजगार के मुद्दे उठाए।



यह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पुसोर ब्लॉक के सुपा गांव में अडानी पावर के प्रस्तावित चरण-3 ताप विद्युत संयंत्र पर कड़ी आपत्तियों पर चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड ने प्रस्तावित परियोजना के लिए एक सार्वजनिक सुनवाई की जिसमें 2×800 मेगावाट अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल तकनीक शामिल है। निगम ने कहा कि यह नौकरियों, औद्योगिक विकास और आर्थिक लाभ पर केंद्रित था, लेकिन स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रचारकों को प्रदूषण, राख, भूजल, कृषि भूमि और पारिस्थितिक क्षति के बारे में गंभीर चिंता

थी। उन्होंने तर्क दिया कि यह क्षेत्र पहले से ही मौजूदा उद्योगों से महत्वपूर्ण वायु प्रदूषण का सामना कर रहा है और एक और बड़ा ताप विद्युत संयंत्र पर्यावरण और स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ा सकता है। स्थानीय निवासियों ने कंपनी के रोजगार के दावों के बारे में भी सवाल उठाए, जिसमें कहा गया कि क्षेत्र में युवाओं से वादा की गई नौकरियां आमतौर पर बाहरी लोगों के पास जाती थीं। कथित झूठे भूमि पंजीकरण पर पिछले संघर्षों ने दुश्मनी को और बढ़ा दिया है। इस प्रकार सार्वजनिक सुनवाई औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण, नौकरियों, भूमि अधिकारों और जवाबदेह विकास के लिए स्थानीय मांगों के बीच एक बड़े संघर्ष का संकेत है।

अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://thelens.in/adani-power-raighar-project-villages-raise-isues-regarding- Pollution-and- Employment/

"ड्रैगन की प्यास जो दक्षिण एशिया के अस्तित्व को खतरे में डालती है": नदियों को कोई सीमा नही पता

इसमें यरलुंग त्सांगपो पर चीन के व्यापक बांध निर्माण के कारण हिंदू कुश हिमालय (एचकेएच) में बढ़ते जल-राजनीतिक तनाव की जांच करता है, जो ब्रह्मपुत्र के रूप में भारत में बहती है। यह तर्क देता है कि क्षेत्रीय संप्रभुता की पारंपरिक वेस्टफेलियन अवधारणाएँ राजनीतिक सीमाओं को पार करने वाली नदियों जैसी जैविक प्रणालियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। पेपर यथार्थवाद और गैरेट हार्डिन की "ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स" के चश्मे के माध्यम से चीन के बांध-निर्माण की जांच करता है ताकि इसे संसाधन संप्रभुता के अभ्यास के रूप में देखा जा सके जो चीन को निचले देशों, विशेष रूप से भारत और बांग्लादेश पर पर्याप्त जल-आधिपत्य लाभ दे सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून की कमियों पर भी जोर देता है, जैसे कि बाध्यकारी प्रवर्तन तंत्र की अनुपस्थिति जो शक्तिशाली राज्यों को जिम्मेदारियों से बचने में सक्षम बनाती है। अंत में, लेख पारिस्थितिक संस्थागतवाद का प्रस्ताव करता है, जो उन क्षेत्रों के कानूनी रूप से बाध्यकारी सहयोग है जहां सीमा पार नदियों को सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है न कि भू-राजनीतिक शक्ति के उपकरण के रूप में।

अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:

https://mvs-beyondthestatehorizon.blogspot.com/2026/07/the-thirst-of-dragon-wich-threaten.html

मछुआरे, प्रकृतिवादी तटीय आर्द्रभूमि को जलाशय में बदलने के प्रभावों के बारे में चिंतित हैं



200 से ज़्यादा मछुआरे वेटलैंड साइट पर ममल्लन जलाशय प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि इससे तटीय इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ेगा, जिस पर उनकी आजीविका निर्भर है। तस्वीर: वेटिवर कलेक्टिव।

200 से अधिक मछुआरे आर्द्रभूमि स्थल पर मामल्लन जलाशय परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं, इस डर से कि तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जो उनकी आजीविका को बनाए रखता है।

यहाँ तमिलनाडु सरकार द्वारा चेन्नई के पास एक तटीय आर्द्रभूमि को छठी प्रमुख जल-भंडारण सुविधा, मामल्लन जलाशय में बदलने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। इस परियोजना को चेन्नई में पानी की बढ़ती मांग और वर्तमान ताजे जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन मछुआरे, प्रकृतिवादी और पर्यावरण समूह आर्द्रभूमि को कुछ और में बदलने के जैविक प्रभावों के बारे में चिंतित हैं। तटीय आर्द्रभूमि महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करती हैं जिनमें मत्स्य पालन का समर्थन करना, जैव विविधता को बनाए रखना, जल प्रवाह को नियंत्रित करना और कई प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करना शामिल है। इसलिए, जलाशय में परिवर्तित इस तरह का पारिस्थितिकी तंत्र स्थानीय आजीविका और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। यह विवाद तेजी से विकासशील आबादी की पानी की जरूरतों को पूरा करने और प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करने के बीच एक बुनियादी संघर्ष को रेखांकित करता है जो अपने आप में जल सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार यह शहरी विकास, पारिस्थितिकीय संरक्षण के बारे में मौलिक विचारों पर प्रकाश डालता है और क्या जल अवसंरचना का उत्पादन करने के लिए आर्द्रभूमि को निकालना चेन्नई की दीर्घकालिक जल आवश्यकताओं का एक स्थायी समाधान है। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:

https://india.mongabay.com/2026/07/a-coastal-wetland-could-soon-beome-a-reservoir-to-met-a-citieswater-demand/

पीयूडीआर (PUDR) की रिपोर्ट में कहा गया है कि 27 महीने के ऑपरेशन कगार के दौरान बस्तर में 607 लोग मारे गए



2014 में बस्तर में इलाके पर नियंत्रण बनाए रखने के अभियान पर सुरक्षा बल। | फ़ोटो क्रेडिट: पवन दाहात

फ्रंट लाइन बस्तर में माओवादी विद्रोह के खिलाफ 27 महीने तक चलने वाली सुरक्षा लड़ाई, ऑपरेशन कगार की मानवीय और संवैधानिक क्षति को देखती है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR) की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 से मार्च 2026 के बीच 607 हत्याएं, 487 गिरफ्तारियां और 1,496 आत्मसमर्पण हुए। मारे गए लोगों में से, PUDR ने 516 को आरोपी माओवादियों, 55 को नागरिकों और 36 को सुरक्षाकर्मियों के रूप में वर्गीकृत किया है।

रिपोर्ट मुठभेड़ हत्याओं, गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण के स्वतंत्र सत्यापन के अभाव के बारे में चिंतित है और बताती है कि सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध अधिकांश जानकारी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से है। यह तर्क देता है कि ऑपरेशन कगार संघर्ष का एक तीव्र सैन्यीकरण है और सवाल करता है कि क्या बल के उपयोग ने राजनीतिक बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान के विकल्पों को हटा दिया है। सुरक्षा बलों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और आत्मसमर्पण और पुनर्वास पर नियम चिंता के विशिष्ट मुद्दे हैं।

इसके अलावा, यह युद्ध को भूमि, वन, खनन और आदिवासी स्वशासन के लिए बड़े विवादों से संबंधित करता है। इसमें तर्क दिया गया है कि पांचवीं अनुसूची, पेसा और वन अधिकार अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए संवैधानिक सुरक्षा उपाय हिंसा की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह राज्य की बढ़ती जवाबदेही, स्वतंत्र जांच और संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानकों के सम्मान की मांग करता है।

अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:
https://frontline.thehindu.com/news/operation-kagar-baster-killings-report/article71245843.ece

जलवायु संबंधी चिंता युवाओं को शक्तिहीन क्यों महसूस करा रही है?



दृश्य श्रेय: परिधि चौधरी

यह भारत में युवाओं के बीच जलवायु चिंता की बढ़ती समस्या पर चर्चा करता है, यह देखते हुए कि जलवायु परिवर्तन की समझ अक्सर एजेंसी की भावना के बजाय भय, शक्तिहीनता, क्रोध और भावनात्मक थकान का कारण बनती है। चार राज्यों में पहली बार मतदान करने वाले 1,600 मतदाताओं के 2024 के एक सर्वेक्षण में, असर ने पाया कि जबकि युवा लोग जलवायु की स्थिति से बहुत अवगत थे, कई लोग अभिभूत महसूस कर रहे थे और नहीं जानते थे कि वे क्या कर सकते हैं जिससे फर्क पड़ेगा। यह आंशिक रूप से इस अंतर को एक जलवायु संदेश से जोड़ता है जो आपदा और तात्कालिकता पर जोर देता है लेकिन भावनात्मक प्रसंस्करण, सांप्रदायिक चिंतन या भागीदारी के लिए कुछ अवसर प्रदान करता है। यह तर्क देता है कि जलवायु चिंता को केवल व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य के मामले के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि असमान बुनियादी ढांचे, अनिश्चित आजीविका, निष्कर्षण विकास और निर्णय लेने से बहिष्कार के रूप में माना जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप पेपर जलवायु शिक्षा को बढ़ावा देता है जिसमें भावनात्मक साक्षरता, बातचीत, समुदाय, एकजुटता और सामूहिक कार्रवाई शामिल है, और नकारात्मक भावनाओं को पारिस्थितिक नुकसान, अन्याय और अनिश्चितता के लिए उचित प्रतिक्रिया के रूप में मान्यता देता है।

अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://asar.co.in/blog/why-climate-anxiety-makes-young-people-feel-powerless/

भारत को अपने डेटा केंद्रों को कैसे सशक्त बनाना चाहिए?

यह देश के ऊर्जा और जल नेटवर्क पर भारत के तेजी से बढ़ते डेटा-सेंटर क्षेत्र के प्रभाव का विश्लेषण करता है, जिसमें पर्यावरणीय स्थिरता और बुनियादी ढांचे के खर्चों के वितरण से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा स्थानीयकरण और बढ़ती डिजिटल मांग से प्रेरित होकर भारत की डेटा सेंटर क्षमता में काफी विस्तार होने की उम्मीद है। छोटी सुविधाएं ज्यादातर वर्तमान विद्युत बुनियादी ढांचे पर निर्भर कर सकती हैं, जबकि गीगावाट-स्केल केंद्रों को बिजली उत्पादन, संचरण, भंडारण और 24 घंटे की विश्वसनीय आपूर्ति में पर्याप्त खर्च की आवश्यकता होती है। इसमें आगाह किया गया है कि इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बढ़ सकती है और बुनियादी ढांचे के खर्चों को औसत ऊर्जा उपयोगकर्ताओं को हस्तांतरित किया जा सकता है। कई राज्य डेटा केंद्रों में निवेश को लुभाने के लिए पर्याप्त सब्सिडी, कर प्रोत्साहन और कम बिजली दरें प्रदान कर रहे हैं। साथ ही, डेटा केंद्रों को ठंडा करने के उद्देश्यों के लिए पानी की महत्वपूर्ण मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों में तनाव बढ़ जाता है। अध्ययन इन निवेशों के लिए एक तर्क के रूप में एआई कंप्यूटिंग के लिए प्रत्याशित मांग की वैधता को चुनौती देता है और तर्क देता है कि भारत को व्यापक डेटा-सेंटर विकास का समर्थन करने से पहले ऊर्जा सुरक्षा, जल संसाधनों, पारिस्थितिक परिणामों और लोक कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://www.carboncopy.info/how-should-india-power-its-data-centres

समुदायों के लिए न्याय और गरिमा सुनिश्चित करना केन-बेतवा नदी का विरोध लिंकिंग परियोजना

यह मध्य प्रदेश में केन-बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना के प्रति आदिवासी, वन-निर्भर समुदायों और किसानों के बढ़ते विरोध की रिपोर्ट करता है, जिसमें जबरन स्थानांतरण, पुलिस उत्पीड़न और पर्यावरण क्षरण के दावों पर जोर दिया गया है। ऑल इंडिया रिवर्स फोरम और नेशनल अलायंस फॉर क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल जस्टिस के साथ मिलकर नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट्स (NAMP) धोधन, पलकौहा, कुपी और खरियानी जैसे गांवों में प्रदर्शनकारियों पर कथित गिरफ्तारी, उत्पीड़न, एफआईआर और बल प्रयोग की निंदा करता है। रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि यह पहल जल स्रोतों, जंगलों, भूमि, आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालती है, विशेष रूप से पर्यावरण की दृष्टि से नाजुक पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर है । समुदायों ने भूमि अधिग्रहण, कम वेतन, वन अधिकारों के उल्लंघन और उचित परामर्श की कमी के बारे में आशंका व्यक्त की है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रभावित समुदायों को एलएआरआर (LRR) अधिनियम, 2013 और

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत सुरक्षा के अधिकार हैं, जिसमें परामर्श, सहमति, मुआवजा और पुनर्वास शामिल हैं।

एनएपीएम (NAPM) कथित रूप से फर्जी एफआईआर को वापस लेने, पुलिस आचरण की निष्पक्ष जांच, जबरन बेदखली और विध्वंस की तत्काल समाप्ति, सम्मानजनक पुनर्वास और परियोजना के सामाजिक, पारिस्थितिक और कानूनी प्रभावों का पूरी तरह से स्वतंत्र मूल्यांकन करने की मांग करता है। यह संघर्ष को आदिवासी अधिकारों, लोकतांत्रिक विरोध, पारिस्थितिक समानता और संवैधानिक स्वायत्तता की सुरक्षा के रूप में स्थापित करता है।

अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:
https://napmindia.org/2026/05/17/ensure-justice-and-dignity-for-communities-resisting-the-ken-betwa-river-linking-project/

कैसे बड़ी तेल कंपनियों ने प्लास्टिक प्रदूषण संधि को अवरुद्ध किया

पेपर प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य समझौता स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं के पतन की जांच करता है, यह तर्क देते हुए कि शक्तिशाली जीवाश्म ईंधन और पेट्रोकेमिकल हितधारकों ने जानबूझकर पर्याप्त प्रगति में बाधा डाली। अगस्त 2025 में जिनेवा में 183 देशों के बीच चर्चा प्रारंभिक संधि या बाद की वार्ताओं पर आम सहमति के बिना संपन्न हुई। लेख उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन को जोड़ता है, जिसने प्लास्टिक निर्माण पर प्रतिबंधों, खतरनाक रसायनों पर नियमों और उत्पादक जवाबदेही को बढ़ाने की वकालत की, एक पेट्रोकेमिकल गठबंधन के खिलाफ जो स्वैच्छिक पहलों को प्राथमिकता देता है जो ज्यादातर अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण पर केंद्रित है। यह चर्चा में उद्योग लॉबिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका और प्रभाव को रेखांकित करता है, जिसमें जीवाश्म-ईंधन और रासायनिक उद्यमों से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसका तर्क है कि प्लास्टिक का निर्माण जीवाश्म-ईंधन के उपयोग के भविष्य के लिए उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण होता जा रहा है, जिससे यह क्षेत्र उत्पादन बाधाओं के लिए अभेद्य हो जाता है। यह इस बात पर जोर देता है कि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए जीवाश्म-ईंधन पूंजी के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव से लड़ने की आवश्यकता है।

अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:

https://jajaipur.blogspot.com/2026/08/blog-post.html

बिहादी एआई टाउनशिप प्लानः

कर्नाटक सरकार की जीबीआईटी परियोजना क्या है और इसमें आग क्यों लगी हुई है

यह बिदादी से सटे कर्नाटक के नियोजित ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप (जीबीआईटी) के आसपास की बहस की पड़ताल करता है, जिसका उद्देश्य भारत का उद्घाटन एआई-संचालित टाउनशिप होना है। व्यापक भूमि पर परिकल्पित, इस पहल का उद्देश्य बेंगलुरु में बढ़ती आबादी और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों को कम करते हुए आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को स्थापित करना है। फिर भी, इस पहल को किसानों के लगातार प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है, जो कृषि भूमि, उनके निर्वाह के साधनों और स्थानीय पारिस्थितिक संसाधनों के संभावित नुकसान के बारे में आशंकित हैं। किसानों ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के बारे में पूछताछ की है, विशेष रूप से अनुमति और परामर्श से संबंधित। पर्यावरण संगठनों और स्थानीय आबादी ने व्यापक वनों की कटाई, भूजल पुनर्भरण और कृषि उपज के बारे में आशंका व्यक्त की है। प्रशासन का तर्क है कि जी. बी. आई. टी. नौकरियों का सृजन करेगा, बुनियादी ढांचे को बढ़ाएगा, और आर्थिक संभावनाएं प्रदान करेगा, और प्रभावित मालिकों को विकसित संपत्ति में मुआवजे या हिस्सेदारी का प्रस्ताव दिया है। इस प्रकार यह विवाद तकनीकी शहरीकरण, भूमि अधिकारों, कृषि आजीविका और पारिस्थितिक स्थिरता के बीच व्यापक संघर्ष को रेखांकित करता है।

अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:

https://timesofindia.indiatimes.com/real-estate/news/bidadi-ai-township-plan-what-is-karnataka-govts-gbit-project-and-why-is-it-under-fire/articleshow/132010701.cms

केंद्र सरकार ने पश्चिमी घाटों में 56, 800 वर्ग किलोमीटर को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र बनाने के लिए अधिसूचना जारी की



मनोहर-मनसंतोषगढ़ सह्याद्री माध्यमिक वन, उत्तरी पश्चिमी घाट, 10 जून, 2026। फोटो: रोहितजाहनवी, सीसी बाय 4.0, विकिमीडिया कॉमन्स के माध्यम से

यह केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गोवा और गुजरात में 56,825.7 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESA) के रूप में नामित करने वाली एक मसौदा अधिसूचना को फिर से जारी करने का विश्लेषण करता है। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार और राज्यों के बीच कई विवादों के बाद आया है, जिसमें सबसे हालिया घोषणा में 60 दिनों की अवधि के लिए सार्वजनिक आपत्तियों और सिफारिशों को आमंत्रित किया गया है। यदि लागू किया जाता है, तो पदनाम खनन, उत्खनन और रेत निष्कर्षण पर प्रतिबंध लगा देगा, वर्तमान खदानों को समाप्त कर देगा, तापीय ऊर्जा और उच्च प्रदूषण व्यवसायों को सीमित कर देगा, और पर्याप्त निर्माण और पनबिजली पहलों की देखरेख करेगा। कर्नाटक के पास संभवतः सबसे व्यापक प्रस्तावित ESA क्षेत्र होगा, जिसके बाद महाराष्ट्र और केरल होंगे। इसमें पश्चिमी घाटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए गाडगिल समिति के 2011 के सुझाव और बाद में कस्तूरीरंगन समिति की संकीर्ण सिफारिश में लगभग 37% क्षेत्र को शामिल करने से उपजी लंबी चर्चा में योजना को प्रस्तुत किया गया है। कम होते क्षेत्र के बावजूद, राज्य विकास की सीमाओं और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के बारे में आशंकाओं का संदर्भ देते हुए इस पहल का विरोध करते रहते हैं।

अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:

https://thewire.in/enenvironment/union-govtreissuesnotificationpropzing-56800-sq-km-as-eco-sensitive-areas-in-Western-ghats

जस्टिस इन माइनिंग नेटवर्क आपकी एकजुटता और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है। हमें लिखें justiceinminingnetwork@gmail.com

संकलनकर्ता - बुधन सिंह सिंकु

सम्पादक - डॉ॰ पी॰एम॰ टोनी